अध्याय - 4 संस्थाओं का कामकाज

स्मरणीय तथ्य

- लोकतन्त्र में जब जनता शासकों का चुनाव करती है तो ये चुने हुए शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं।
- संविधान के द्वारा शासन के मूल्यों के निर्धारण के साथ संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं की कार्य सीमा का भी निर्धारण किया जाता है ।
- भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिए 27 % स्थान आरक्षित किया गये ।
- इससे पहले आरक्षण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (S.C./S.T.) को ही दिया जा रहा था।
- भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता वी.पी. मंडल (विंदेश्वरी प्रसाद मण्डल) ने की। इसी कारण इसे मंडल आयोग कहते हैं ।
- पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया ।
- मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980ई. में प्रस्तुत की जिसमें प्रमुख थी, सरकारी नौकरियों में सामाजिक, और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देना ।
- दूसरा पिछड़ी जाति आयोग :
  - 1979 में गठित।
  - अध्यक्ष - बी. पी. मंडल ।
  - 8 सितम्बर 1993 में पूरी तरह लागू ।
- **संस्था :** नागरिको की आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास,कल्याण परक सुविधाएँ नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को ही संस्था / संस्थाएँ कहा जाता है ।
- संसद : भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं ।
- **संसद :** संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून / विधि निर्माण का कार्य करते हैं ।
- संसद के दो सदन होते हैं : a. लोकसभा b. राज्य सभा
- संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं:
  - भारत का नागरिक हो ।
  - सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो।
  - दिवालिया या सज़ायाफ्ता न हो ।
- संसद के राजनैतिक अधिकार :
  - कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानून की जगह नये कानून बनाने का अधिकार ।
  - सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार ।
  - सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण का अधिकार ।
  - सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार ।
- लोकसभा (हाउस ऑफ पीपल / लोअरहाउस): लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं । इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है । इसके सदस्यों की संख्या 543 + 2 होती है। (2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है ।)
  - सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रुप से होता है।
  - मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण।
- राज्यसभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स / अपर हाउस): राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है । इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।
  - सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
  - मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं।
  - राज्यों के सम्बन्ध में विशेष अधिकार।
- लोकसभा और राज्य सभा में अंतर :
  - लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है।
  - राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है।
  - संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है।
  - लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारो का प्रयोग करती है।
  - लोकसभा मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है । राज्यसभा को यह अधिकार नहीं ।
- **कार्यपालिका :** सरकार की नीतियों को कार्यरूप देनेवाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं।
- कार्यपालिका के दो हिस्सा होते हैं :-
  - राजनैतिक कार्यपालिका :- प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद् मिलकर राजनैतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। मंत्रीपरिषद् का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना या क्रियान्वयन करना। इसलिए मंत्रीपरिषद् को कार्यपालिका कहा जाता है। राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं।
  - स्थायी कार्यपालिका :- यह नौकरशाहों से मिलकर बनी होती है । नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। सरकारें बदलने के बावजूद नौकरशाहों यानी स्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है ।
- प्रधानमंत्री:- प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वह देश की सबसे

महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता ।वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जबतक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है ।

- राष्ट्रपति:- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है जो बहुमत या गठबंधन या सदन में जिनको बहुमत हासिल हो, की सरकार बनती है ।
- मंत्रिपरिषद् :- मंत्रिपरिषद् उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं । इसमें आम तौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं ।
- मंत्रियों की रैंक इस प्रकार है :-
  - कैबिनेट मंत्री :- अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार दिया जाता है। परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 25 होती है ।
  - स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री :- इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है । ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं।
  - राज्यमंत्री :- अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
- भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार :-
  - कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता।
  - विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय ।
  - विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी।
  - मंत्रियों के कामों का वितरण।
  - किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार ।
- राष्ट्रपति : भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं ।
  - सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है।
  - जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह कानून बन पाता है।
  - सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है ।
  - सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं।
- भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं :-
  - भारत का नागरिक हो ।
  - आयु 35 वर्ष से अधिक हो ।
  - दिवालिया या सजायाफ्ता न हो ।
  - सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो ।
  - लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो ।
- न्यायपालिका :- एक महत्वपूर्ण संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निबटारे का अधिकार होता है । देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है ।
- न्यायपालिका के अधिकार :- इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवादो के निबटारे का अधिकार होता है ।
- भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम :-
  - पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय ।
  - राज्यों में उच्च न्यायालय।
  - जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय ।
- गठबंधन सरकारः- विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार।
- कार्यपालिकाः व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फ़ैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है।
- सरकारः- संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन-जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है।
- विधायिकाः- जन प्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है।
- कार्यालय ज्ञापनः- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फ़ैसले या नीति के बारे में बताया जाता है।
- राजनैतिक संस्थाः- देश की सरकार और राजनैतिक जीवन के आचार को नियमित करनेवाली प्रक्रियाओं का समूह।
- आरक्षणः- भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें 'आरक्षित' करने की नीति ।
- राज्यः- निश्चित क्षेत्र में फैली राजनैतिक इकाई, जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। 'राज्य' शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाईयों या प्रांतों के लिए भी होता है। इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय स्तर पर "भारत की सरकार" को और किस नाम से जाना जाता है ?

a. केन्द्र/संघ की सरकार
b. राज्य सरकार
c. पंचायत की सरकार
d. नगरपालिका की सरकार

2. भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया?

a. 1969 ई. b. 1979ई.

c. 1985ई. d. 1990 ई.

3. दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था?

a. हर्षा चौहान b. विजय सांपला

c. बी०पी० मंडल d. डॉ भीम राव अम्बेडकर

4. दूसरा पिछडा जाति आयोग को किस नाम से जाना जाता है?

a. मंडल आयोग b. कमंडल आयोग

c. योजना आयोग d. स्वर्ण सिंह आयोग

5. मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की?

a. 17% b. 25%

c. 30% d. 27%

6. 1989 ई. के लोकसभा चुनाव के बाद किस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनी ?

a. कांग्रेस पार्टी b. जनता दल

c. भारतीय जनता पार्टी d. बहुजन समाजवादी पार्टी

7. 1989 ई. के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने ?

a. राजीव गांधी b. इंद्र कुमार गुजराल

c. अटल बिहारी वाजपेयी d वी० पी० सिंह

8. इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला संबंधित है –

a. पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने से संबंधित

b. अनुसूचित जातियों को के आरक्षण से संबंधित

c. अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित

d. इनमें से कोई नहीं।।

9. पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने संबंधी भारत सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ठहराया ?

a. अवैध b. वैध

c. फैसला नहीं दिया d. असंवैधानिक

10. भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि कहाँ बैठक करते हैं?

a. विधान सभा में b. कांग्रेस में

c. ग्राम पंचायत में d. संसद भवन में

11. राज्य या प्रांतीय स्तर में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है ?

a. संसद b. राज्य सभा

c. विधानसभा d. लोकसभा

12. कानून बनाने या विधि निर्माण करने का कार्य करती है-

a. कार्यपालिका b. न्यायपालिक

c. राष्ट्रपति d. विधायिका

13. सरकार की नीतियों को कार्यरूप या लागू करने का कार्य करती है –

a. कार्यपालिका b. न्यायपालिका

c. राज्यपाल d. विधायिका

14. कानून की समीक्षा और रक्षा करती है

a. न्यायपालिका b. राष्ट्रपति

c. विधायिका d. कार्यपालिका

15. संसद क्या कार्य कर सकती है?

a. नए कानून बना सकती है।

b. मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है।

c. मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नये कानून बना सकती है।

d. उपरोक्त सभी।

16. भारतीय संसद के अंग है –

a. लोकसभा b. राज्य सभा

c. राष्ट्रपति d. उपरोक्त सभी

17. हमारे देश के संसद में कितने सदन हैं?

a. चार b. दो

c. तीन d. एक

18. संसद के दोनो सदनों का नाम क्या है?

a. लोकसभा और राज्यसभा

b. लोकसभा और विधान सभा

c. राज्यसभा और राष्ट्रपति

d. विधान सभा और नगरपालिका

19. संसद के फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होते है ?

a. प्रधानमंत्री b. राष्ट्रपति

c. राज्यपाल d. मुख्यमंत्री

20. वर्तमान में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव कराए जाते हैं?

a. 443 b. 500

c. 525 d. 543

21. राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है?

a. 150 b. 200

c. 250 d. 300

22. राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनित करते हैं?

a. 10 b. 12

c. 15 d. 20

23. राज्य सभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है?

a. 14 दिन b. 20 दिन

c. 28 दिन d. 7 दिन

24. निम्न में कौन ब्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है ?

a. लोकसभा के विपक्ष का नेता

b. राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को भी चाहे

c. लोकसभा में बहुमत दल का नेता

d. इनमें से कोई नहीं।

25. क्या होगा? अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें "मंत्रिपरिषद्" पर विश्वास नहीं है।

a. प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा।
b. प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री अपने पद पर बने रहेगें।
c. प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है ।
d. इनमें से कोई नहीं।।

26. कार्यपालिका के कितने भाग होते हैं ?

a. एक b. दो
c. तीन d. चार

27. निम्नलिखित में कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है?

a. शिक्षा मंत्रालय का सचिव
b. न्यायाधीश
c. पुलिस महानिदेशक
d. शिक्षा मंत्री

28. निम्नलिखित में कौन स्थायी कार्यपालिका है ?

a. शिक्षा मंत्री b. राष्ट्रपति
c. गृह सचिव d. संसद का अध्यक्ष

29. भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है ?

a. राष्ट्रपति b. प्रधानमंत्री
c. मुख्यमंत्री d. राज्यपाल

30. प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है?

a. राष्ट्रपति b. लोकसभा का सभापति
c. मुख्य न्यायाधीश d. इनमें से कोई नहीं।।

31. अगर ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो संसद का सदस्य नहीं है। उस व्यक्ति को कितने समय के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है?

a. 1 वर्ष के भीतर b. 9 महीने के भीतर
c. 6 महीने के भीतर d. 3 महीने के भीतर

32. भारत के मंत्रिपरिषद् में कौन-कौन स्तर के मंत्री होते हैं?

a. कैबिनेट स्तर के मंत्री
b. स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री
c. राज्य मंत्री
d. उपरोक्त सभी

33. कैबिनेट या मंत्रिमंडल को कार्य करने में मदद कौन करता है ?

a. प्रधानमंत्री b. राज्यपाल
c. राष्ट्रपति d. कैबिनेट सचिवालय

34. कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

a. प्रधानमंत्री b. राज्यपाल
c. राष्ट्रपति d. लोकसभा का सभापति

35. प्रधानमंत्री का कार्य है –

a. मंत्रिपरिषद् के विभिन्न विभागों का समन्वय करता है।
b. सारे मंत्री प्रधान मंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं।
c. प्रधानमंत्री,मंत्रियों के कामों का वितरण और पुनर्वितरण करता है।
d. उपरोक्त सभी।

36. भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है?

a. प्रधानमंत्री b. राष्ट्रपति
c. मुख्यमंत्री d. उप-राष्ट्रपति

37. लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षो का होता है?

a. 4 वर्ष b. 5 वर्ष
c. 6 वर्ष d. 7 वर्ष

38. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है–

a. 2 वर्ष b. 3वर्ष
c. 6 वर्ष d. 8 वर्ष

39. राष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है?

a. जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
b. लोक सभा के सदस्यों द्वारा
c. राज्य सभा के सदस्यों द्वारा
d. संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा

40. सारे कानून और केन्द्र सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले किसके नाम से जारी होते हैं?

a. राष्ट्रपति
b. प्रधानमंत्री
c. लोकसभा के सभापति
d. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

41. राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्तियाँ करता है?

a. भारत के मुख्य न्यायधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य न्यायालयों के न्यायधीशों
b. राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों
c. दूसरे देशों में राजदूतों को
d. उपरोक्त सभी

42. सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि- समझौता किसके नाम से होता है?

a. प्रधानमंत्री
b. राष्ट्रपति
c. राज्यपाल
d. कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्री

43. भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है ?

a. थल सेना का अध्यक्ष b. प्रधानमंत्री
c. उप-राष्ट्रपति d. राष्ट्रपति

44. राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसकी सलाह पर करता है?

a. लोक सभा b. न्यायपालिका

c. राज्य सभा d. मंत्रिपरिषद्

45. संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कब कानून बन जाता है?

a. प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद
b. राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद
c. मंत्रिपरिषद् की मंजूरी के बाद
d. न्यायपालिका की मंजूरी बाद

46. भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है?

a. प्रधानमंत्री
b. राष्ट्रपति
c. लोकसभा का सभापति
d. सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश

47. संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होता है –

a. अमेरिकी सरकार का मुखिया
b. अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष
c. a और b दोनों
d. इनमें से कोई नहीं।।

48. अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

a. तीन वर्ष b. पांच वर्ष
c. चार वर्ष d. छः वर्ष

49. संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की विधायिका को किस नाम से जाना जाता है?

a. संसद b. नेशनल असेंबली
c. अमेरिकी कांग्रेस d. स्टेट्स-जेनराल

50. हमारे देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है?

a. कार्यपालिका b. विधायिका
c. न्यायपालिका d. इनमें से कोई नहीं।

51. भारत में पूरे देश के लिए कौन-सा न्यायालय है?

a. सर्वोच्च न्यायालय b. उच्च न्यायालय
c. जिला न्यायालय d. स्थानीय स्तर के न्यायालय

52. राज्यों के स्तर पर कौन-सा न्यायालय होता है ?

a. सर्वोच्च न्यायालय b. उच्च न्यायालय
c. जिला न्यायालय d. इनमें से कोई नहीं।

53. भारत में जिला स्तर पर कौन-सा न्यायालय होता है?

a. सर्वोच्च न्यायालय b. उच्च न्यायालय
c. जिला न्यायालय d. इनमें से कोई नहीं।

54. भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है?

a. कोलकाता b. चंडीगढ़
c. पटना d. नई दिल्ली

55. झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है?

a. राँची b. लातेहार
c. जमशेदपुर d. दुमका

56. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है तो, इसकी सुनवाई कौन-सा न्यायालय करता है ?

a. उच्च न्यायालय
b. सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय
c. जिला न्यायालय
d. इनमें से कोई नहीं।

57. फौजदारी और दीवानी मामले में अपील करने के लिए सर्वोच्च संस्था है-

a. उच्च न्यायालय b. सर्वोच्च न्यायालय
c. जिला न्यायालय d. इनमें से कोई नहीं।।

58. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है?

a. प्रधानमंत्री b. राष्ट्रपति
c. लोक सभा का अध्यक्ष d. राज्यपाल

59. सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन-सा न्यायालय करता है?

a. सर्वोच्च न्यायालय
b. उच्च न्यायालय
c. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय
d. जिला अदालतें

60. इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला में सर्वोच्च न्यायालय के कितने वरिष्ठ न्यायधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं ?

a. 11 b. 15
c. 07 d. 17

61. पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के भारत सरकार के आदेश को, सही ठहराते हुए, सर्वोच्य न्यायालय ने क्या संशोधन करने के लिए सरकार को कहा ?

a. सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
b. पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
c. पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा घटा देनी चाहिए।
d. उपरोक्त में से सभी

बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर

1.	a	2.	b
3.	c	4.	a
5.	d	6.	b
7.	d	8.	a
9.	b	10.	d
11.	c	12.	d

13.	a	14.	a
15.	d	16.	d
17.	b	18.	a
19.	b	20.	d
21.	c	22.	b
23.	a	24.	c
25.	a	26.	b
27.	d	28.	c
29.	a	30.	a
31.	c	32.	d
33.	d	34.	a
35.	d	36.	b
37.	b	38.	c
39.	d	40.	a
41.	d	42.	b
43.	d	44.	d
45.	b	46.	a
47.	c	48.	c
49.	c	50.	c
51.	a	52.	b
53.	c	54.	d
55.	a	56.	b
57.	b	58.	b
59.	c	60.	a
61.	b		

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है?

उत्तर- एक लोकतंत्र में शासको को विभिन्न प्रकार के नियम-कानून और संस्थाओं के भीतर रहकर काम करना पड़ता है। इसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते है।

2. हमारे देश में फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तीन प्रमुख संस्थाएँ कौन-कौन सी है?

उत्तर- हमारे देश में फैसले लेने में भूमिका निभाने वाली तीन प्रमुख संस्थाएँ हैं- विधायिका कार्यपालिका, न्यायपालिका।

3. एस. ई. बी. सी. का पूर्ण विन्यास क्या है?

उत्तर- एस. ई. बी. सी. शब्द का पूर्ण शब्द विन्यास है सोशली एंड एजुकेशनली बैंकवर्ड क्लासेज (सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग) है।

4. भारत सरकार द्वारा 1979 ई. में गठित दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य क्या था ?

उत्तर- दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करना और उनका पिछड़ापन दूर करने का उपाय बताना था।

5. मंडल आयोग के सिफारिशों को किसने लागू किया?

उत्तर- मंडल आयोग के सिफारिशों को जनता दल के नेता प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने लागू किया।

6. मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी?

उत्तर- भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाए।

7. संसद के दो सदन - राज्य सभा और लोक सभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है ?

उत्तर- a. राज्य सभा को 'अपर हाउस'' या 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' के नाम से भी जाना जाता है।

b. लोकसभा को 'लोअर हाउस' या 'हाउस ऑफ पीपल' के नाम से भी जाना जाता है।

8. संसद का संयुक्त अधिवेशन से क्या समझते हैं?

उत्तर- जब किसी सामान्य कानून को पारित करने में संसद के दोनों सदन - लोक सभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो जाता है तो अंतिम फैसला लेने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इसे ही संसद का संयुक्त अधिवेशन कहते है ।

9. कार्यपालिका के कितने हिस्से या भाग होते है ?

उत्तर- कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं - a. राजनैतिक कार्यपालिका। b. स्थाई कार्यपालिका।

10. राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है?

उत्तर- राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या' पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

11. अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन-सा फैसला खुद कर सकते हैं?

a. अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं।

b. लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं।

c. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।

d. मंत्रीपरिषद् में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं।

उत्तर- c. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं।

12. निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है?

a. जिला अधिकारी

b. गृह मंत्रालय का सचिव

c. गृह मंत्री

d. पुलिस महानिदेशक

उत्तर- c. गृह मंत्री

13. न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है?

a. संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरुरत होती है।

b. अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है।

c. न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है।

d. अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है।

उत्तर- a. संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरुरत होती है।

14. निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन-सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है?

a. सर्वोच्च न्यायालय b. राष्ट्रपति

c. प्रधानमंत्री d. संसद

उत्तर- d. संसद

15. उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा:

a. देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है।

b. ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएँ सुलभ कराई जाएँगी।

c. सार्वजनकि वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूँ की कीमतें कम जाएँगी।

d. पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा।

e. ऊँची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढाए जाएँगे ।

उत्तर- a. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

b. संचार और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय

c. कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

d. स्वास्थ्य मंत्रालय

e. रक्षा मंत्रालय

16. देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती हैं:

a. सड़क, सिंचाई, जैसे बुनियादी ढाँचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा।

b. स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है।

c. दो राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है।

d. भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना माँगती है।

उत्तर- a. लोकसभा (वित्त मंत्रालय)

b. संसद

c. सर्वोच्च न्यायालय

d. कार्यपालिका

17. भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता ? निम्नलिखित चार जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष में कारण दीजिए।

a. संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है।

b. लोकसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है।

c. चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है।

d. प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च आएगा।

उत्तर- a. सर्वथा उपयुक्त है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो। यह उसे कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है क्योंकि उसे मंत्रीपरिषद् के साथ काम करना पड़ता है।

18. तीन दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज की जरूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का, बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज खतरनाक है।। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है। कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है?

उत्तर- ऐसी फिल्म अव्यहारिक तथा अलोकतांत्रिक है। किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है। साथ ही सुधारों के लिए अत्यधिक योजना बनाने की जरूरत होती है। मैं शंकर कि बातों से सहमत हूँ। राज्य में बदलाव लाने के लिए केवल एक दिन काफी नहीं होता।

19. एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने दो छात्राओं को अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया। यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकतीं थी और अगर चाहें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों?

उत्तर- मैं कृत्रिम लोकसभा को प्राथमिकता दूंगा क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्शिाली होती है। कोई भी सामान्य बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। किन्तु लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है। वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियाँ अधिक होत हैं। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। देश के प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है।

20. आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर तीन विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग-अलग प्रतिक्रिया थी। इसमें से कौन-सी प्रतिक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है?

a. श्री निवास का तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है।

b. अंजैया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती थी । सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।

c. विजया का मानना है कि न्यायपालिका न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है। बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन-सा विचार सही है?

उत्तर- न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अंजैया का विचार सही है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भारतके अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? और एकीकृत न्यायपालिका से क्या समझते हैं?

उत्तर- भारत में विभिन्न स्तरो पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से 'न्यायपालिका' कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उनका फैसला मानना पड़ता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय किस तरह की विवाद की सुनवाई करता है?

उत्तर- सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी' मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। वह निम्नलिखित किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है.

a. देश के नागरिकों के बीच के विवाद की।

b. नागरिकों और सरकार के बीच के विवाद की।

c. दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच के विवाद ।

d. केन्द्र और राज्य सरकार के बीच के विवाद ।

3. "राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में स्वविवेक से कार्य करता है।" एक उदाहरण दे कर बतायें।

उत्तर- राष्ट्रपति के स्वविवेक कार्य को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने 'विवेक' से काम लेता है। वह ऐसे नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है।

4. प्रधान मंत्री के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन करें।

उत्तर- सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। जो निम्नलिखित हैं-

a. वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

b. वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय और सामान्य निगरानी करता है।

c. विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है।

d. प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है।

e. उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है।

f. प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ती करता है।

5. राजनैतिक और स्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं?

उत्तर- किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो भाग होते हैं-

a. राजनैतिक कार्यपालिका।

b. स्थायी या गैर राजनीतिक कार्यपालिका ।

a. राजनैतिक कार्यपालिका- जनता द्वारा एक निश्चित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहा जाता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार से जुड़े होते हैं। ये राजनैतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। सरकार से जुड़े सभी मंत्रीगण राजनैतिक कार्यपालिका ही हैं।

b. स्थायी या गैर राजनीतिक कार्यपालिका- ये लोकसेवाओं मे काम करने वाले सिविल सर्वेंट या प्रशासनिक सेवक होते हैं। ये सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पद पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनैतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हुए रोजमर्रा के प्रशासन में मंत्रियों की सहायता करते हैं।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय संसद, जनता की ओर से कई तरह के राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। स्पष्ट करें।

उत्तर- भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। भारत की संसद जनताकी ओर से कई तरह से राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। जिसे निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है –

a. कानून या विधि निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य भारत की संसद करती है। भारत की संसद नए कानून बना सकती है,मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है,मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नये कानून बना सकती है।

b. भारतीय संसद सरकार चलाने वालों अर्थात कार्यपालिका पर सीधा और पूर्ण नियंत्रण रखती है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चल सकती है।

c. सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद की मंजूरी के बाद ही सरकार, सार्वजनिक पैसे को खर्च कर

सकती है।

d. सार्वजनिक मसलों और देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही' सर्वोच्च संस्था है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है।

2. लोकसभा, राज्यसभा से किस प्रकार अधिक शक्तिशाली होता है? तीन कारण बताए। या "अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास हैं न कि राज्यसभा के पास।" स्पष्ट करें।

उत्तर- हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। इसे निम्नलिखित बिन्दू से स्पष्ट किया जा सकता है –

a. किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। लेकिन मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन में अंतिम फैसला होता है। लोकसभा के सदस्य- संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोक सभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है।

b. लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई विधेयक पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। लोक सभा राज्य सभा के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

c. लोकसभा मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर 'विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है।

3. केन्द्र-सरकार या संघ सरकार के मंत्रिपरिषद् का गठन का वर्णन करें।

उत्तर- सर्वप्रथम, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री और इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद् कहा जाता है। मन्त्रीपरिषद् में तीन स्तर के मंत्री होते हैं। जो निम्न हैं –

a. कैबिनेट मंत्री - ये प्रायः सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद् के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद् का शीर्ष समूह होता है।

b. स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री - ये मंत्रिपरिषद् के दूसरे स्तर के मंत्री है जो प्राय: छोटे मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। साधारणत: ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं।

c. राज्य मंत्री- ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं।

सरकार के फैसले कैबिनेट मंत्रियों के बैठकों में किए जाते हैं। मंत्रियों की राय और विचार अलग- अलग हो सकती है लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है।